# दिल्ली विधान सभा

### समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार,20 फरवरी,2006/फाल्गुन 01,1927(शक)

संख्या: 129

## गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानि कि 17 फरवरी,2006 तक विधान सभा सचिवालय को 25 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के लिये निर्धारित कार्यदिवस,शुक्रवार, 03 मार्च,2006 को चर्चा के लिये लिया जायेगा:-

<u>क्र.सं.</u>	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय
1.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली विधान सभा के सदस्यों को मेट्रो के मुफत पास प्रदान किये जाएं।
2.	श्री साहब सिंह चौहान	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली को तुरन्त प्रभाव से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए।
3.	श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी	यह सदन संकल्प करता है कि गांवों के ग्रामीण स्वरूप से छेड़छाड़ न की जाए और जो गांव शहरी घोषित हो चुके हैं उन्हें गांवों की ही श्रेणी में वापिस लाया जाये और साथ ही उन्हें हाउस टैक्स और भवन उप-विधियों से मुक्त रखा जाए।

सिद्धार्थ राव सचिव

### DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Monday, 20<sup>th</sup> February 2006 / 1 Phalguna 1927 (Saka)

#### No. 129

1:

Hon'ble Members are hereby informed that notices for Twenty-five resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e. Friday, 17<sup>th</sup> February 2006. The following three resolutions have been selected on the basis of balloting. These would be taken up for discussion on the Private Members Day i.e. Friday the 3rd March 2006:

SI. No.	Name of the Member	Text of the resolution
1	Shri O.P. Babber	"This House resolves that free metro passes be provided to the Members of the Delhi Assembly."
2	Shri Sahab Singh Chauhan	"This House resolves that Delhi be granted full statehood with immediate effect."
3	Shri Ramvir Singh Bidhuri	"This House resolves that rural status of the villages should not be altered and those villages which were declared as urbanized be restored in the category of villages and simultaneously exempt them from House tax and building byelaws."

Siddharath Rao Secretary